The house reassembled after lunch at fortynine minutes past two of the clock

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. KAUSHIK) in the Chair.

**STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE COAL MINES NATIONALISATION LAWS (AMENDMENT) ORDINANCE, 1986 (NO.7 OF 1986) PROMULGATED BY THE PRESIDENT OF THE 7TH OCTOBER, 1986 AND THE COAL MINES NATIONALISATION LAWS (AMENDMENT) BILL, 1986.**—contd.

**श्री अश्विनी कुमार** (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हम लोग कोल नेशनलाइजेशन बिल के प्रति चर्चा कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि न्यायालय में कुछ समस्याएं हैं पिट हैड्स के बारे में उसको दूर करने के लिए, नियमानुसार करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। इस सम्बन्ध में मेरा इतना ही निवेदन है उपाध्यक्ष, महोदय, कि सन् 1971 में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ और यह सन् 1986 का अन्त आ गया है, 16 वर्ष व्यतीत हो गये। अभी तक जिनका माल लिया गया है, उनको कितना कंपनसेशन देना है, कैसे देना है, इसका निराकरण नहीं हो सका है। लगभग डेढ़ दशक बीत गया है, पीढ़ियां बदल रही हैं। इसमें कुछ ऐसी समस्याएं खड़ी हो रही हैं जिनकी ओर मैं विशेष करके आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिस समय कोल का राष्ट्रीयकरण हुआ आपने कम्पनी ले ली, उसकी एसेट्स ले लीं, लेकिन उस दिन उस कम्पनी के ऊपर बैंक का जो ओवरड्राफ्ट था वह आपने नहीं लिया। बैंक के ओवरड्राफ्ट के ऊपर ब्याज बढ़ता चला जा रहा है। 16 साल में कितना ब्याज बढ़ जायगा, क्या समस्या होगी, क्या देनदारी होगी, यह विषय है। जिनसे सब कुछ ले लिया वह तो देनदार नहीं रहे। आप कह सकते थे यह हम नहीं ले सकते, इसे सम्भालो। लेकिन वह रकम 16 साल के बाद साधारण ब्याज की दर से भी तिगुनी चौगुनी हो जायगी इसका कौन देनदार होगा। या फिर 15 वर्ष हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के मुकदमें में जायगा? इसके बारे में निराकरण चाहूंगा।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने राष्ट्रीयकरण किया, बहुत अच्छा किया, कई समस्याओं का निराकरण किया। 15 साल बीत गए हैं। जिनको जो देना है वह देकर छुट्टी कीजिए। इतना ही मेरा निवेदन है।

आज कोयला खदानों में उत्पादन का लक्ष्य रखा है 2000 में 418 मिलियन टन तक पहुंचाने का। यह देश की आवश्यकता को देखते हुए बहुत आवश्यक है। परन्तु आज जो कोल इंडिया की कार्य प्रणाली चल रही है उसको देखते हुए कई बार शंकाएं उत्पन्न होती हैं। मंत्री महोदय स्वयं शंका प्रकट करते हैं। पत्र-पत्रिकाओं में उनके आर्टिकिल आते हैं और लगता है जैसे वे हमारी भाषा बोल रहे हैं—सरकार में भी है और विरोधी दल में भी।

**एक माननीय सदस्य** : वे आपकी भाषा नहीं बोल रहे हैं, वे आपका मन्तव्य टटोलना चाहते हैं।

**श्री अश्विनी कुमार** : मंत्री भी रहें और विरोधी दल के नेता भी बनें, यह संगत नहीं लगता।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. KAUSHIK): Don't listen; you go on.

**श्री अश्विनी कुमार** : कोल इंडिया साल में 6 चेयरमैन बदल चुके हैं। अब जो नए आए हैं उनको एक साल बीत चुका है। जिसको एपोइन्ट करें उसको काम करने दीजिए, उसकी रेस्पांसिबिलिटी और एकाउन्टबिलिटी बनाइए। जब किसी का रिटायरमेंट का समय आता है तो उसको एक्सटेंशन देना है या नहीं देना है यह पहले से निश्चित होना चाहिए। यह पहले से मालूम होता है कि कौन रिटायर करने जा रहा है।

[श्री अश्विनी कुमार]

बीच में जो गैप हो जाता है और उस कारण स्टाप-गैप अरेंजमेंट होते हैं वह कोल के प्रोडक्शन की दृष्टि से बहुत डिमारलाइजिंग होते हैं।

एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब काम पूरा नहीं होता है तो फिगर इन्फ्लेट कर दिए जाते हैं। समाचारपत्रों में छपा है कि सैन्ट्रल कोल फील्ड में 3 मिलियन टन कोयले की फिगर इनफ्लेट हुई, पकड़ी गई। इसी तरह से तीन साल पहले प्राफिट एण्ड लास में इनफ्लेशन हुआ था। पता लगा कि चेयरमैन साहब अपने एक्सटेंशन के लिए सारा मेनीपुलेशन कर रहे थे। यह धांधली आज भी हो रही है।

मैं एक और घटना की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। अभी-अभी पिछले दिनों बोकारो जोन के अन्दर एक नए प्रकार का इनफ्लेशन हुआ है। जितना कोयले का प्रोडक्शन है उससे बढ़ाकर पेमेंट किया गया है। जो करने वाले अधिकारी थे उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ है, परन्तु मजदूरों से डिडक्शन किया जा रहा है। मेरा कहना है कि इसके सम्बन्ध में मंत्री महोदय तहकीकात करें। जो इनफ्लेशन टाप लेवल पर जनरल मेनेजर या दूसरे अफसर करते हैं उनको दोषी नहीं ठहराया जाता है। मेरा कहना यही है कि जो इस प्रकार का काम करने वाले है उनके ऊपर अंकुश लगाया जाय। दूसरी एक बात की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी जो रिपोर्ट आयी है उस में लिखा है कि आउटपुट पर मैन शिफ्ट .89 से .84 हो गया है। यह जो घटा है यह भी एक चिन्ता का विषय है। उत्पादकता घट रही है जब कि हमारे यहां कोल खदानों में ओपेन कास्ट माइन्स की संख्या हम बढ़ाते चले जा रहे हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है। पुरानी माइन्स की जो समस्या है उन में प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है लेकिन ओवर आल प्रोडक्शन में प्रीडक्टिविटी घटे यह एक चिन्ता का विषय है। जब कि हमारे मंत्री जो विदेशों का उदाहरण देते हैं कि आस्ट्रेलिया में वह 2.5 टन है। मैं इस ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इसको गलत ढंग से मैनीपुलेट करने का प्रयत्न हो रहा है। कई जगहों पर खदानों में लेबरर्स के नाम पर जो अधिकारी हैं उनको नौकर दिये जा रहे है। कई जगह 400, 500 वर्कर्स डोमेस्टिक सर्वेंट्स कर के रख लिये गये हैं और उनका नाम वहां खातों में चढ़ा हुआ है कि वे खदानों में काम कर रहे हैं। सारे अधिकारियों को सर्वेंट्स एलाउन्स मिल रहा है। तो यह एक समस्या है। उनसे घर का काम लेना एक इल्लीगल प्रेक्टिस है और इसके कारण भी आउट-पुट घट रहा है। इस ओर मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि इस तरह की जो घटनायें हो रही हैं उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

अंत में मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि हमारे पास मैनपावर है। आज क्या उसका प्रापर यूटिलाइजेशन हो रहा है। क्या प्रापर मोटिवेशन उसको है ? मैं समझता हूं कि इस का अत्याधिक अभाव है। जैसा कि मंत्री जी ने कहा है मजदूरों को मैनेजमेंट में भागीदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने प्रयोग किये हैं और दुर्गापुर का उदाहरण वे खुद देते हैं कि यह प्रयोग अच्छा रहा है। लेकिन हमारी कोल माइन्स जो इतनी महत्वपूर्ण हैं, जिन पर हमारी सारी अर्थ व्यवस्था आधारित है जो हमारी इनर्जी की बेस हैं और उन से हमारी इनर्जी पालिसी गाइड हो रही है उसके बारे में ठीक प्रकार से सोचने का प्रयास करना चाहिए। उसका जो स्ट्रक्चर है उस को ठीक प्रकार से एनालाइज़ करना चाहिए। मैं खदानों में गया हू और वहां की एकाउन्टेबिलिटी का एक उदाहरण देना चाहता हूं। कोलियरी लेविल पर एक एकाउन्ट्स का अधिकारी है। एरिया लेबिल पर एक अधिकारी है, पर जब कंपनी लेबिल पर आते हैं तो वहां 8 टायर सिस्टम है जिसमें कोई रेस्पांसिबिल नहीं होता। हम जब पता लगानें गये कि वहां फीगर इंफ्लेट हुआ है और इस के लिये कौन रेस्पांसिबिल

है तो फाइनेंस डाइरेक्टर निकल गया, नीचे के अधिकारी निकल गये और बीच में से किसी को इस्केप गोट बना दिया जाता है। कोल इंडिया में भी 5 टायर सिस्टम है। धरातल पर काम करने वाला एक व्यक्ति है लेकिन वहां 8 टायर सिस्टम है। तो इसमें रेस्पांसिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि अगर इंफ्लेटेड फीगर्स आये हैं तो उसके लिये जिम्मेदार कौन है। तो कोल इंडिया को जैसा एक्सपर्ट मैनेजमेंट उन्होंने दिया है उसके हिसाब से इसको देखें कि वहां पर कितने आदमी चाहिए। मेरी धारणा है कि हमारा मैनेजमेंट टाप हैवी है। वर्कर्स पर बहुत बोझ है और हमारे काम की क्षमता घट रही है जिस के कारण काम करने वाला रोता है कि हम काम कर रहे हैं और कोयले का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं और ऊपर के अधिकारी केवल रोब गांठते हैं और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यह तमाम जिम्मेदारी मैनेजिंग डाइरेक्टर की होनी चाहिए। मैं आप के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का सिस्टम यहां पर लाने के बाद ही देश में कोयले की कायदे से पूर्ति होने वाली है।

अंत में कहना चाहता हूं कि प्रोजेक्ट एक्जीक्यूशन में और डिसीजन को लेने में देरी होती है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि ई० सी० एल० में 18 प्रोजेक्टस सब्मिट किये गये। 1130 करोड़ के। तीन वर्ष से उन के क्लियरेंस की आशा की जा रही है। वह 1130 करोड़ अब 22 सौ करोड़ हो गया होगा या 2400 करोड़ हो गया होगा इसके लिये कौन जिम्मेदार होगा। इस डिले के लिये कौन
3 P.M. जिम्मेदार है ? इतना ही नहीं जब ऐक्जीक्यूशन में जाते हैं तो 1973 में जो 35 प्रोजेक्ट 80 करोड़ रुपए के बनाने थे उनमें से 11 तो 56 करोड़ रुपए में पूरे हो गए और 24 अभी बाकी हैं और उन पर 752 करोड़ रुपए लगने की बात कही जा रही है। तो डिले और इनऐफिशियेंसी तथा डिले इन डिसीजन से जो घाटा हो रहा है उसको आप मिनिस्ट्री लेवल पर और कोल इंडिया लेवल पर स्ट्रीमलाइन करें जिससे कि धरातल पर काम हो सके।

अंत में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपने नई नीति बनाई है, अभी तक की जो नीति है वह उसके विपरीत है क्योंकि अभी तक यह नीति थी कि जिसकी जमीन अक्वायर की जाती थी उसके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाती थी। यह आपने बन्द कर दिया। इसके कारण मुझे यह बताया गया है कि बिहार में कई जगह लैंड ऐक्विजिशन में समस्या आ रही है, लैंड आपको नहीं मिल रही है, खदानें कम हो रही हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मनुष्य की मौलिक आवश्यकता है इंप्लायमेंट की जिसकी ओर कोल इंडिया लिमिटेड का ध्यान नहीं है। लोगों को इंप्लायमेंट देने का उसका दायित्व है। तो उस पर पुनर्विचार करके आप जिस प्रकार से भी उनको जमीन प्राप्त हो सके वसा उपाय करें ताकि कोल इंडिया लिमिटेड अच्छा काम कर सके।

**श्री कल्पनाथ राय** (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, कोयला खान राष्ट्रीयकरण विधि संशोधन विधेयक जो सरकार द्वारा इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सर्व-प्रथम मैं कोयला खान मंत्री श्री साठे जी को देश की करोड़ों जनता की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके मंत्रित्व काल में कोयले का उत्पादन भी बढ़ा है और बिजली की दशा में भी सुधार हुआ है। यह बड़ा ही सराहनीय कार्य हुआ है। बिना दोनों के, कोयला और बिजली के देश का विकास नहीं हो सकता।

**[उपसभाध्यक्ष (डा० बापू कालदाते) पीठासीन हुए]**

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, 1973 में कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया जो कि बहुत ही अच्छा कदम था समाजवाद की दिशा में। 1969 से

[श्री कल्पनाथ राय]

1973 तक हिन्दुस्तान में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, राजाओं के प्रिवी पर्स समाप्त हुए, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण हुआ और 1976 में भारत के संविधान में हमने संशोधन करके समाजवादी कल्याणकारी राज्य का संकल्प लिया।

महोदय, इस समय देश में बहुत ही निरर्थक बहस चल रही है। सरकारी और गैर-सरकारी पार्टियों की तरफ से कि हमारी पार्टी और हमारे मंत्री श्री वसंत साठे जी पब्लिक सैक्टर के खिलाफ हैं या समाजवाद के खिलाफ हैं। मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी और हमारी सरकार के मंत्री साठे जी समाजवादी विचार के कट्टर साथी रहे हैं, समाजवाद में इनकी गहरी आस्था है और समाजवाद की दिशा में इन्होंने सराहनीय कदम उठाए हैं। यह बिलकुल निरर्थक बहस देश में चल रही है कि हमारी पार्टी प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में है। हमने 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुसविदा बनाया है उसमें हमने स्वीकार किया है कि "पब्लिक सैक्टर विल आक्यूपाइ कमांडिंग हाइट्स आफ अवर इकानामी"। प्राइवेट सेक्टर की ज्यादती और जुल्मों के खिलाफ ही दुनियां में पब्लिक सेक्टर आया। पूंजीवाद की निरंकुशता के खिलाफ ही दुनियां में समाजवाद आया। हमारी आजादी की लड़ाई के दौरान हमारे राष्ट्र के नेताओं ने समाजवाद की स्थापना का संकल्प किया था। मैं इस अवसर पर 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ में कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से जो भाषण दिया था उसकी ओर आपका ध्यान दिलाता हूं। उन्होंने कहा ——

The problem of socialism cannot be solved without socialism. I am a socialist. When I say I am socialist, I mean scientific socialist. The problem of poverty and unemployment in India cannot be solved without socialism and I want to convert Congress into a socialist organisation.

यह 1936 में उन्होंने कहा। 1938 में प्लानिंग कमेटी जो बनी उसके वे चेयरमैन बने। लगातार समाजवाद की दिशा में कांग्रेस पार्टी में समाजवाद की आवाज बन कर जवाहरलाल जी बोलते रहे और उस समाजवाद को एक अर्थ देने का काम श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया। महान कदम थे बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, राजाओं के प्रिवीपर्स को समाप्त करना और कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण करना। अगर आप चाहते हैं कि कोयला खादानों का प्रोडेक्शन बढ़े तो कोयले की मैनेजमेंट में आप को आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा।

मैंने पहले भी इस बात को कहा था और फिर कहता हूं कि माफिया गैंग कोल खानों में धनबाद में, झरिया में काम कर रहा है। राजनीतिक दलों के लोग उसमें इन्वाल्व हैं। इसमें करोड़ों रुपये की लूट हो रही है, अरबों रुपये का फर्जी भुगतान हो रहा है। धनबाद में, अकेले धनबाद में 300 मर्डर हुए हैं। एक नेता ने जिसने 300 मर्डर कराये हैं वह विरोधी दल के नेताओं का बहुत बड़ा चहेता है और जयप्रकाश नारायण के सपनों का हिन्दुस्तान बनाना चाहता है ...

**श्री चतुरानन मिश्र** (बिहार) : अगर यह कहते हैं कि विरोधी दल तो उसमें हम लोग, सभी लोग आ जाते हैं। क्या यह माननीय सदस्य के लिए कहना यह आम बात उचित है? अगर यह कहना है तो हिम्मत करके कहें कि उसका यह नाम है।

**श्री कल्पनाथ राय** : मैंने आपसे कहा है कि एक नेता ने कराये हैं जो श्री जयप्रकाश नारायण के सपनों का हिन्दुस्तान बनाना चाहता है। इसके बावजूद भी अगर चतुरानन मिश्र जी की समझ में नहीं आता है तो क्या करें।

**श्री चतुरानन मिश्र** : कम समझदार आदमी को भी सदन में रहने का अधिकार है। नाम लेने में क्या एतराज है?

**श्री कल्पनाथ राय** : पिछले 10 वर्षों से बात होती रही है। कोयला खादानों में कोयला खोदने का काम हमारे मजदूर करते हैं मगर कोयले को पिट से उठा

कर दिल्ली तक, पंजाब तक पहुंचाने का काम, ट्रांसपोर्ट का काम माफिया गैंग के हाथ में रहता है। सारी लोडिंग और अनलोडिंग का काम माफिया गैंग के हाथ में रहेगा। सभी कांट्रेक्ट माफिया गैंग के हाथ में रहेंगे। यूनियनों के नाम पर फर्जी वसूली होती रहेगी। मजदूर, इंजीनियर, आवरसीयर जो वहां काम करते हैं वे डर के मारे फर्जी पेमेंट करते हैं माफिया को। कई इंजीनियर्स गोली से उड़ा दिये गये माफिया गैंग के द्वारा। कोयला खादानों में सबसे ज्यादा कौन लूटेगा इसका एक कंपीटिशन चलता है माफिया में। और इसमें सभी राजनीतिक लोग शामिल हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक आप, जैसे एक बार्डर सेक्योरिटी फोर्स है वैसे ही कोयला सेक्योरिटी फोर्स नहीं बनाते तब तक उन लोगों का भला होने वाला नहीं है। मजदूर रात भर डर के मारे घूमते रहते हैं। रात को उनको पकड़ कर ले जाते हैं और उनसे 20–20 रुपये मांगते हैं और अगर वह मजदूर नहीं देता तो उसको गोली से उड़ा दिया जाता है। उनको पुलिस का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अगर कोई मर्डर में फंसता है तो वह बचा लिया जाता है। जिस आदमी ने 300 मर्डर कराये हैं वह आज विधायक बना हुआ है।

**श्री अश्विनी कुमार :** विधायक भी है, संसद् भी है और कितने ही हैं। सब दलों में है।

**श्री कल्पनाथ राय :** लेकिन जिसने तीन सौ मर्डर कराये हैं वह विरोधी पार्टी में है।

**श्री अश्विनी कुमार :** क्यों नहीं आपकी सरकार उनको पकड़ कर बन्द करती है। आपकी सरकार वहां पर है। यहां पर भी है और वहां पर भी है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार उनसे मिली हुई है।

**उपसभाध्यक्ष (डा० बापू कालदाते) :** इनका भी कहना यही है। वह आपके साथ हैं। इसमें सब राजनीतिक दल के लोग हैं।

**श्री कल्पनाथ राय :** जिसने तीन सौ हत्याएं कराई हैं वह विरोधी दल का है। वह एम०एल०ए० बना हुआ है। जय प्रकाश नारायण के सपनों का भारतवर्ष बनाना चाहता है। और जिस दल का उसको समर्थन है वह दल भी नपुंसक हो चुका है। दलों में सही बात कहने की क्षमता नहीं है। आज हमारे देश में स्थिति यह है कि खदानों में काम करने वाले मजदूरों में क्षमता नहीं है। इन मजदूरों की पर-केपिटा इनकम कैसे बढ़ेगी? श्री चतुरानन मिश्रा जी अभी आंकड़े दे रहे थे, विदेशी मजदूरों की बात कह रहे थे। विदेशी मजदूरों को मैंने भी देखा है। वे बड़े हट्टे-कट्टे तन्दुरस्त हैं, अच्छी तनख्वाहा पाते हैं और एक अच्छी जिन्दगी जीते हैं। इसलिए वे जो प्रोडक्शन करते है वह भी अच्छा होता है और ज्यादा होता है। लेकिन हमारे देश में यह स्थिति है कि जिन लोगों को कोई काम नहीं मिलता वे मजदूरी का काम करते हैं। वे अपना घरबार छोड़ जाते हैं तो कुछ लोग उनके सामने बन्दूक लेकर आ जाते हैं। उनको मारते हैं, उनकी लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं, उनको कत्ल करते है। पुलिस उनकी बात नहीं सुनती है, सरकार उनकी बात नहीं सुनती है और विरोधी दल के लोग अपना चंदा इकट्ठा करने के काम में लगे रहते हैं। समाज वाद का सपना इस प्रकार से पूरा नहीं हो सकता है। कितने ही ब्यूरोक्रेटस और इंजीनियर धनबाद और झरिया में मारे जा चुके हैं। एक लाख का पैमेंन्ट हैं तो आप इन गुण्डों को और माफिया गग वालों को जब तक 50 हजार की पैमेन्ट नहीं करेंगे तब तक वे जिन्दा नहीं छोड़ते हैं। वे उनकी लड़की का किडनैप कर लेंगे, उसके लड़के का किडनैप कर लेंगे। पुलिस उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है। यह स्थिति धनबाद और झरिया के इलाकों की है। ऐसी स्थिति में हिन्दुस्तान के खदानों के मजदूरों की पर-केपिटा इनकम कैसे बढ़ेगी। उनकी इनकम तभी बढ़ सकती है जब वे डिसिप्लिन में रहें। किसी भी समाजवादी देश में हड़ताल नहीं होती है? लेकिन हमारे देश में तो हड़ताल आम बात हो गई है। आज तक मजदूरों ने इस बात

[श्री कल्पनाथ राय]

के लिए हड़ताल नहीं कि उनको अच्छी सुविधा दी जायें। उनकी हड़ताल के कारण राजनैतिक होते हैं। अगर हमारे मजदूर अपनी समस्याओं को हल करने के लिए अधिक मेडिकल फेसिलिटीज देने के लिए अच्छे क्वार्टर देने के लिए मांग करेंगे तो उसका हम सब लोग समर्थन करेंगे। जैसा मैंने कहा, किसी भी समाजवाद देश में हड़ताल नहीं होती है। अगर हमें अपने देश में समाजवाद की स्थापना करनी है तो समाजवाद और जनतंत्र साथ-साथ नहीं चल सकते हैं। हिन्दुस्तान एक विकासशील देश है। मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में 10 वर्षों के लिए हड़तालों पर बैन लगा देना चाहिए। मारेटोरियम आन स्ट्राइक्स होना चाहिए। अगर हमें इस देश में समाजवाद लाना है तो जनतंत्र और समाजवाद साथ-साथ नहीं चल सकते हैं। क्या चीन में हड़ताल होती है? क्या रूस में हड़ताल होती है? क्या चेकोस्लोवाकिया में हड़ताल होती है?

**श्री चतुरानन मिश्र** : : क्या वहां पर टाटा और बिरला हैं?

**श्री कल्पनाथ राय** : उन देशों में कभी हड़ताल नहीं होती है। लेकिन हिन्दुस्तान में हड़ताल करना धर्म हो गया है। बंगाल में कम्यूनिस्ट पार्टी पावर में हैं। वहां पर क्या हालत है। वहां पर गरीबी बीमारी और तबाही के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। बंगाल के अन्दर इन लोगों ने क्या काम किया है? वहां पर तबाही के अलावा कुछ नहीं है। क्या इसी को समाजवाद कहते हैं? रूस में इतनी तरक्की कैसे हुई? वहां पर कोई भाषण नहीं कर सकता है, कोई अपनी विचारधारा का प्रचार नहीं कर सकता है। कोई कविता नहीं लिख सकता है, मजदूर अपनी बात नहीं कह सकता है, इसलिए वहां पर तरक्की हुई है। दूसरी तरफ जिन देशों में पूंजीवादी व्यवस्था है, उन्होंने दुनिया के देशों को लूट कर अपना पैसा बढ़ाया है। जर्मनी फ्रांस, इंगलैण्ड और अमेरिका आदि देशों में पूंजीवादी व्यवस्था है। उन्होंने दूसरे देशों के बल पर अपनी पूंजी बढ़ाई है। वहां के मजदूर की स्थिति भी अच्छी है। हिन्दुस्तान एक विकास के रास्ते पर चलने वाला राष्ट्र है, विकासशील देश है। अभी स्थिति यह है कि जनतंत्र और समाजवाद एक साथ नहीं रह सकते हैं। हमें समाजवाद लाना है तो कुछ त्याग भी करना पड़ेगा।

पेट की आजादी होगी और मन की भी आजादी होगी। यहां सैकुलरिज्म भी होगा और उसके साथ साथ नेशनलिज्म भी रहेगा, यहां डेमोक्रेसी रहेगी और सोशलिज्म भी रहेगा। दुनिया के जितने आदर्श सिद्धांत हैं उन सभी सिद्धांतों को हमने अपने संविधान में रूप दे दिया है। हम इस मुल्क में समाजवाद चाहते हैं। आज ये लोग प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेटाइजेशन का जो नारा लगा रहे हैं मैं कहना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू की नीतियों से या श्रीमति इंदिरा गांधी की नीतियों से जो लोग हटने की कोशिश करेंगे और उससे हटने की कोशिश कर रहे हैं, वह देश के लिये बड़े ही दुर्भाग्य की बात होगी। कांग्रेस पार्टी में हमेशा माइनारिटी में लोग प्रगतिशील नीतियों के साथ रहे हैं। हमारा बहुमत हमेशा प्रतिक्रियावादी शक्तियों के साथ रहा है। चाहे कांग्रेस का विभाजन हो, चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चाहे राजाओं के पिर्वी पर्स का मामला हो, तो केवल 25 प्रतिशत लोग श्रीमति इंदिरा गांधी के साथ थे। लेकिन भारत की करोड़ों करोड़ प्रगतिशील जनता उनके साथ थी।

**उपसभाध्यक्ष (डा० बापू कालदाते)** : अब समाप्त कीजिये।

**श्री कल्पनाथ राय** : इसलिए उन्होंने इसमें विजय प्राप्त कर ली।

**उपसभाध्यक्ष (डा० बापू कालदाते)** : समाप्त कीजिये।

**श्री कल्पनाथ राय** : विरोधीदल प्राइवेट सेक्टर, मोनोपोली हाउसेज के साथ धर्म और धरती के नाम पर प्राइवेट सेक्टर के अलम्बरदार बने हुए हैं और अगर कोई समाजवाद का नाम ले रहा है तो, उपसभाध्यक्ष महोदय, माफ कीजिये, नाम लेगें बाबू जयप्रकाश नारायण का और काम क्या करेंगे, कातिलों को अपने

आस्तीन में लेकर घमते रहेंगे। जब ऐसा होगा तो कैसे समाजवाद आयेगा ? जयप्रकाश नारायण का सपना कैसे पूरा होगा। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के संविधान में और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में कहा था कि समाजवाद की स्थापना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने आवडी कांग्रेस में सोशलिस्ट स्ट्रक्चर आफ दि सोसायटी की बात कही और काभराज की अध्यक्षता में 1962 में सहकारिता समाजवाद की आधारशिला होगी की बात की। लेकिन सबसे बड़ा श्रेय भारत की जनता जिसको देती है, जिसको सैल्यूट करती है, श्रीमति इंदिरा गांधी, भारत के संविधान के प्रियंबल में है कि :

India is a socialist democratic state. We are committed to socialism.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BAPU KALDATE): You have to stop.

THE KALPNATH RAI: Yes, within two minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BAPU KALDATE): You cannot carry on like this.

अब आप कृप्या खत्म कीजिए।

**श्री कल्पनाथ राय :** दो मिनट के अंदर।

**उपसभाध्यक्ष (डा० बापू कालदाते) :** बिल्कुल दो मिनट में समाप्त कर ही दीजिये।

**श्री कल्पनाथ राय :** आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय हम सोशलिज्म की स्थापना करने के लिए कमिटेड हैं। हम पब्लिक सेक्टर को रखेगें क्योंकि वी आर कमिटेड बाई कांस्टिट्यूशन। जब भारत के संविधान में पविर्त्तन होगा तभी हम प्राइवेट सेक्टर को मानेंगे। मुझे विश्वास हैं कि समाजवादी नेता श्री वसंत साठे जी के नेतृत्व में कोल और इनर्जी के क्षेत्र में ज्यादा उत्पादन होगा और वे ज्यादा से ज्यादा इनर्जी पैदा करेंगे, कोल पैदा करेंगे ताकि हमारा जो देश का चतुर्दिक विकास करने का सपना है, जो हमारे नेता राजीव गांधी का सपना वह चरितार्थ हो। मैं आशा करता हुं कि वे समाजवाद की स्थापना करने और कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों के हित में काम करेंगे। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BAPU KALDATE): Mr. Chaturanan Mishra.

SHRI CHATURANAN MISHRA: I should reply to the debate.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BAPU KALDATE): Very shortly because we have to compete this debate.

**श्री चतुरानन मिश्र :** उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे सहमत हुं कि इसको शार्ट में हो कहा जाय।

**उपसभाध्यक्ष (डा० बापू कालदाते) :** शार्ट भी जरा शार्ट ही रहें।

**श्री चतुरानन मिश्र :** वही कह रहा हूं। उपसभाध्यक्ष, महोदय जो माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं, जाहिर बात है कि अपने अपने दृष्टिकोण से सबों ने विचार व्यक्त किये हैं, लेकिन एक बात तो है कि सभी चाहते हैं कि कोयला उद्योग की तरक्की हो, इसका विकास किया जाए और इसकी कास्ट में कमी लाई जाय। इस लिए कि यह हमारा बैसिक उद्योग है और इसकी तरक्की पर देश की तरक्की निर्भर करेगी। यह बात है, जिस पर हमें सभी को साथ लेकर चलना चाहियें जहां तक यह बात है, उस दिन मंत्री महोदय ने कहा था कि बिना उनके लेख को पढ़े ही हमने संभवतः दूसरों के बारे में भी उन्होंने कहा था कि अपने विचार प्रकट कर दिये प्राइवेट सेक्टर का उन्हें एडवोकेट कहा। वैसे मैं जानता हूं कि हमारे मंत्री महोदय जो हैं उनके इस पर अलग विचार हैं लेकिन लेख में जो बात आई है इसका स्पष्टीकरण हो जाना जरूरी है इसीलिए हम इस बिन्दु को उठा रहे है हम उन के मोटिव पर डाउट कर रहे हैं, एसी बात नहीं है। मैं उनके लेख से एक उददरण देना चाहता हूं कि जो टाइम्स आफ इंडिया तथा दूसरे अखबारों में प्रकाशित हुआ है उस लेख का एक वाक्य यह है कि :

"...worse, by making most of the public sector areas monopolistic, we have eliminated the basic eliment of efficiency i.e. competition."

[श्री चतुरानन मिश्र]

अभी तक कांग्रेस पार्टी की नीति रही है कि हम इकोनोमी के कमांडिंग हाइट्स पर पब्लिक सेक्टर को ले जाना चाहते हैं।

**श्री कल्पनाथ राय:** अभी भी है।

**श्री चतुरानन मिश्र :** अच्छी बात है। अब हम लेख की बात कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर को मजबूत करने अभी आपके वित्त मंत्री ने असर्ट किया है, आप लोग सभी असर्ट कर रहे हैं तो इसको होना ही है। अगर इधर-उधर हो रहा था तो रूक जाएगा इसकी पतवार आपके हाथ में ही है। हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं पहले यह पालिसी उनकी निर्धारित रही है, सभी जानते हैं, अभी भी कह रहे हैं तो अच्छी बात है लेकिन जब इस में मंत्री महोदय कहते हैं मोनोपोलिस्टिक हो गया है पब्लिक सेक्टर तो इसका मतलब क्या है। जब वह कमांडिंग हाइट्स पर आएगा तो यह जाहिर बात है कि देश के जो प्राइवेट सेक्टर के उद्योग रहेंगे उनसे बढ़ कर के आएगा। यह होना ही है। इसको मोनोपालिस्टिक नहीं कहते हैं। कहीं करप्शन हो, कहीं क्वालिटी खराब हो गई हो यह मोनोपोली नहीं हुई आम तौर पर मोनोपालिज की क्वालिटी खराब नहीं होती है यह पब्लिक सेक्टर के बारे में हम को शिकायत है लेकिन वहां यह बात नहीं है मोनोपली कट थ्रोट कम्पीटीशन करता वह उसको जनविरोधी रहता है पब्लिक सेक्टर जन विरोधी नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं, मंत्री महोदय ने कहा है कि कम्पीटीशन होना चाहिये, इसका दूसरा अर्थ क्या है? वह यह है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वह पब्लिक सेक्टर के कम्पीटीशन में आवें। कम्पीटीशन का अर्थ होगा कि खानगी क्षेत्र सम्पूर्ण रूप से प्रतिस्पर्धा करे। तब तो दूसरी मार्किट भी खोली जाए। इसका मतलब यह है कि कमांडिंग हाइट्स नहीं होगी तो ऐसी बात कही जा सकती है नहीं तो इसको स्पष्ट करना होगा कि मोनोपालिस्टिक का क्या मतलब है। अभी तक ति यह रही है कि आप पब्लिक सेक्टर को कमांडिंग हाइट्स पर ले जाना च हैं और धीरे धीरे उस पद्धति में प्राइवेट सेक्टर कमजोर होगा फिलहाल नहीं होगा आगे चल कर के होगा वही दिशा और निर्देश आप किये हुए हैं। इसी लेख के कारण हम ने यह कहा था कि मन्त्री महोदय जो रास्ता ले रहे हैं जहां तक कोयला उद्योग का ताल्लुक है प्राइम मिनिस्टर थेचर भी हिम्मत नहीं कर सकी कि एक साल की हड़ताल के बाद भी इसका राष्ट्रीयकरण तोड़ा जाए जाहिर है कि साठे जी तो ऐसा विचार रखते भी नहीं हैं इसलिए यह सम्भव नहीं है कि खानगीकरण किया जा सके। अंत में, एक दो बात और कह देना चाहता हूं। सुरक्षा को बहुत अंडरमाइन किया गया है। इस बीच में उसकी ओर मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह इसलिए नहीं कि प्राइवेट सेक्टर से तुलना करें तो अभी खराब हुआ है, हम साफ कह देंगे कि प्राइवेट सेक्टर में जो सुरक्षा का इंतजाम था उससे कहीं ज्यादा अच्छा इंतजाम अभी है। इस में कोई दो राय नहीं होनी चाहिये। लेकिन अभी जो झरिया खदान में एक्सीडेंट हुआ जिसमें 6 आदमी मारे गये हमारे डी०जी०एम० एस० वहां गये तो उनको रिकार्ड हीं मिलता है, हमारे ही अफसर कागज-पत्र गायब कर दें तो यह बात नहीं है। जब कोई दुर्घटना होने वाली होती है या छत गिरने वाली होती है तो सबेरे से 10–15 घंटे पहले से ही थोड़ी थोड़ी आवाज आने लगती है जिसको हमारे मजदूर अच्छी तरह समझते हैं हम लोग भी थोड़ा सा समझते हैं लेकिन मजदूर ज्यादा समझते हैं। आवाज आ रही थी इतने पर भी मजदूरों को मजबूर कर दिया कि भीतर जाओ। मन्त्री महोदय को यह भी मालूम है कि हमारे अफसरान हैं या सुपरवाइजरी स्टाफ के लोग हैं वे आजकल मांइस के अन्दर नहीं जाते हैं। वहां बहुत अरक्षा का वातावरण पैदा हो गया है। इसका मन्त्री जी जरूर ध्यान रखेंगे। यह दो बिन्दु थे जिनकी ओर मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। जहां तक मोशन का सम्बन्ध है उससे तो हमें कोई मतभेद था ही नही हम ने शुरू में ही कह दिया था यह मोशन तो रेगुलरलाइज करने के लिए आया है। बहुत पहले ही आ जाना चाहिये था, अगर बहुत पहले आ जाता तो अच्छा होता हम तो अपना मोशन वापिस कर ही

लेंगे इसमें कोई बात नहीं है ।

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI VASANT SATHE): Mr. Vice-Chairman, Sir, at the outset I want to thank all the hon. Members who have participated in this debate and really raised the debate on a very high level discussing not only the coal sector, but, if I may say so, in keeping with the whole tenor of the economic situation, they discussed, in fact, the economic situation, particularly with reference to the public sector.

As Shri Chaturanan Mishraji has just said what is the criticism that was made about my so-called anti-socialist statement. I think it was a loaded criticism. Because of that Shri Mishraji has read out one line. But I will read out some portion to show that there could be nothing greater distortion of my statement than to allay what I have said anything against the objective of socialism or even the concept of public sector.

Sir, in the article which is, in fact, a part of the revised edition of my book was reproduced in the "Times of India" as series. In the very first part, second page I begin by saying "After having quoted certain figures of our growth that we have achieved and as I said a miraculous growth by any standard in the production of power from 1700 MW to 48,000 MW in a period of 30 years is not a small achievement." Having said that, I said "yet the fact remains that contrary to the expectations of the founding fathers of our Constitution and that of the great visionary Jawaharlal Nehru, we have not been able to achieve a balanced growth in the living conditions of our people. We have not been able to provide productive employment to overwhelming majority of employable members of our population. Disparities of income have to be abridged. Economic growth has become narrow and its benefits are confined to small sections of our population." This is how I began by quoting Jawaharlal Nehru.

Then coming to the question of socialism at page 243. this is what I have stated: "In our Constitution we adopted a principle of establishing a sovereign, socialist, secular democratic republic. We as a nation are, therefore, committed to the establishment of a socialist democracy. By socialism in a democratic set up it was envisaged that we would be establishing men who are born equally would continue a casteless and classless society where all men who are born equally would continue to be treated as equals—where there would be equality of opportunity for all and where there will be no exploitation of man by man."

Please tell me: can there be a clearer statement of the objective of socialism in the democracy? I began by saying this and then my anguish that is expressed is unfortunately, however, today socialism has come to acquire a totally distorted connotation in India. And I say initially when we adopted the planning process which had worked successfully in socialist countries, it was felt that as a via media for a democratic society we would create a public sector where utilising national public resources mainly in the core infra-tructural industries we would be able to develop an industrial base which being free from exploitation and exploitory motivations would achieve faster growth and thus acquire commanding heights in the economy of our country. I do not understand anyone can take any exception to this proposition? Then Sir, the line which Chaturanan Ji was just reading out... (*Interruptions*)

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): Sir, it would be very kind of a Minister if he circulates one copy of the book to each Member of the House.

SHRI VASANT SATHE: Sir, I say, this article. I will circulate. As far as the book is concerned, a revised edition in paper pack also has come. It is prized only Rs. 15|. If you kindly afford to do that much, I will be highly obliged because Sir, it is a principle that you never read a book that is presented to you free.

**श्री चतुरानन मिश्र :** एक बात और है सर एवनार्मल बातलिख दीजिए किताब मुफ्त भी बहुत बिकती है ।

श्री वसंत साठे : एबनार्मल नहीं लिखो है। (व्यवधान)

श्री चतुरानन मिश्र : हम आपके बारे में नहीं कह रहे हैं।

श्री वसन्त साठे : यू आर राइट। एबनार्मल नहीं लिखा, इसलिए नहीं बिको।

Chaturanan Ji also in his note holy cow and the cow-boy which he has published has stated the various reasons why public sector is not working efficiently. Sir, I have also, while giving reasons, most of them actually tally with Chaturanan Jis' own statement, I say Sir, we have invested Rs. 6,000 crores, the people of India, the Parliament of India, after nationalising coal sector had not been stingy. They had been generous enough. They said, alright, take whatever money you want. At the time of nationalisation, in total, investment in coal industry was Rs. 50 crores and the producton was 77 million tonnes but exploitation of workers, the slaughter mining was so rampant that the entire coal industry was practically getting destroyed. That was the need for nationalisation and after that, did the people of India through their Parliament hesitate in giving fund? No. you will see, Sir, Rs. 6,000 crores have been invested by now and my anguish was that the causes of dismal performance primarily lie with the adoption of a wrong concept of socialism which equates overemployed, top-heavy, inefficient and unaccountable public sector with socialism. This is what my grievance is?

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): In all industries. .

SHRI VASANT SATHE: Wherever this criteria applies, such an equation becomes wrong and then I further clarify and I quote:

"What is more having set up the publicsector, we started treating it as a holy cow and considered it blasphemous even to question the performance of public sector units."

यह जरा सुन लीजिए, होली काउ का मतलब क्या है।

"Mere questioning was considered to be reactionary. We forgot that in socialistic societies not only the public sector but practically the entire economic activity is managed and controlled by single ideologically dedicated, committed and accountable political party"

This is what my friend, Kalp Nath Rai, was saying.

"In Indian situation we have left the public sector in the hands of an ideologically indifferent service whch is not accountable for its performance and results."

Can you quarrel with this statement, Chaturananji? I don't think any person who claims to have even an elementary conviction about socialism or socialistic principles can differ from this. And then that sentence comes:

"Worse, by making most of these public sector areas monopolistic we have eliminated a basic element of efficiency; that is, competition."

Competition, not with private sector but competition even amongst public sector has to be there; otherwise, even in a running race unless you know that some mark is there which you have to reach, you will never be able to do it; you will become complacent. So, the element of reaching targets is inherent. . .

SHRI SUKOMAL SEN: Even in banks.

SHRI VASANT SATHE: Among banks also there is competition. There is competition amongst nationalised banks. I am saying this. . . .

SHRI CHATURANAN MISHRA: Competition for corruption?

SHRI VASANT SATHE: That also I have said. So, you will agree with me. I again said:

"We also tend to follow a policy of continued top management. We continued to rely on an inherited bureaucratic philosphy of colonial past based on distrust even in this crucial area of development and thus imposed a restricted tenure of two years for the

top management. We kept most of the final decision making financial powers in the hands of bureaucracy, not the Government. Further, by overmanning these sectors we practically ensured that this core, public sector industries would be neither competitive nor economically viable."

This is what I have said. And about private sector they are again and again saying that I am in favour of privatisation of this. I have said in so many words—

"Thus, in the name of Indian socialism all that we have achieved is a stagnant, high cost, inefficient, uncompetitive, irresponsible and unaccountable system of production"...

SHRI JAGESH DESAI: We don't agree.

SHRI VASANT SATHE: It is a different matter if you don't agree. There may be exceptions.

"With such a base in the core sector of our economy the private sector found it lucrative to exploit it for the growth of the consumer industries at the cost of the investment in the public sector. A whole army of those who flourish on contracts for various works, a *nouveau riche* class, came into existence. Much of the income that get funnelled into private hands with public investment escaped income assessment, thus increasing the vast reservoir of unaccounted money."

Now, I know what Mr. Jagesh Desai and some others are saying. There are exceptions. There are public sector units which are run efficiently, which are run with a sense of accountability and, therefore, which are showing results. The whole tenor of my argument is that, I gave the example of coal, I gave the example of steel and I gave the example of power generation.

SHRI JAGESH DESAI: With regard to power generation, it is higher in the Central sector than in the private sector.

SHRI VASANT SATHE: Sir, I cannot have a running dialogue like this.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BAPU KALDATE): Mr. Desai, please let him speak. Yes, Mr. Sathe, you continue.

SHRI SUKOMAL SEN: I want to say one thing, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BAPU KALDATE): No, please. After all, he has to say what he has to say and let him continue.

SHRI VASANT SATHE: If you want, you can ask questions at the end.

SHRI SUKOMAL SEN: Sir, I only wanted to say that this is a very good advertisement for his book at your and our cost!

THE VICE-CHAIRMAN (DR BAPU KALDATE): No disturbance, please. Please carry on, Mr. Sathe.

SHRI VASANT SATHE: It is because, Mr. Sen, you all misquoted me and, therefore, you are getting it now.

Now, Sir, even in the power sector, the State Electricity Boards are also the public sector units and they are not in the private sector. The Central NTPC is a public sector undertaking. The State Boards, several State Electricity Boards, are doing well and the Central undertakings are doing well. While several State Boards are doing well, by and large, there are also exceptions, particularly in the Northern belt, where they are not doing well.

SHRI KALPNATH RAI: Very correct.

SHRI VASANT SATHE: Wherever they are not doing well, you will find that the criteria that I have mentioned apply. Because of all those factors like unaccountability, etc. such a thing has happened.

Now, Sir, I want to deal a little with a basic issue. If in our country we want to utilize our excellent natural resources such as iron ore, bauxite, coal, river waters, these and all such natural resources, with excellent manpower, intelligent manpower. Sir, what is the way that we should go about it? After all, in any activity there has to be cost benefit and a surplus has to be generated. Even

[Shri Vasant Sathe]

in what is known as State capitalism which is one step towards a socialistic society, even in a socialist country, socialism is not the ultimate end, but the ultimate and is communism and, as you know very well, Sir, the withering away of the State has to take place if communism is to be brought about. And, Sir, how does that happen? I am reminded of a story.

Sir, some time back, an international conference of the communist countries was held in China and delegates from all the communist States of the world had come over there. They were all debating as to which State had established communism. After everyone tried to make his claim, a small voice was heard from the corner and it said, "My State". Everybody looked at him and asked: "Who are you?" He said, "I am one Chatterjee. I come from West Bengal." Then everybody looked at him. He asked, "What do you want to say?". They replied, "We have never heard of such a State. What are you talking?"

SHRI SUKOMAL SEN: When did it happen?

SHRI VASANT SATHE: Only recently. (*Interruptions*). You just hear me. Do you know what he said? You would never have heard such a thing. He said precisely what I am going to say. He said, "Because the State has withered away. This is how we have succeeded in establishing communism." (*Interruptions*). This is what ultimately bringing about communism means. But we are at a stage where in our country, with all these resources, if you want that productive activity must take place, then cost-bonefit ratio has to be considered and if that has to be considered, then we must realise that we are not living in isolation in the world and we have to do certain things. But I am not saying that you should reverse the trend. we cannot do that and I know that you cannot retrench so many people. But at least one thing we can do. We can increase our production.

SHRI KALPNATH RAI: Correct.

SHRI VASANT SATHE: And therefore, I have made it very clear, abundantly clear, in my entire thesis in the Book, this participation, all these mafias and other things my friend and other friends have mentioned. You must have a direct, full, effective and real participation of workers in the management in the public sector at least. At least in the public sector, why should we have this concept of employer-employee? If we say that this is the State towards socialism, then at least there let us do away with employers. The management of Coal-India is not an employer. He is also an employee. Why should all the work-force not be treated as partners? If you do that, Sir, we keep away our vested interests, all trade unions, because there is no room for trade unionism then. As Mr. Kalpnath Rai said in a socialist system or where the public sector is a tool for the objective of socialism, no employer-employee concept is there. Therefore, you do not have trade unions in the Soviet Union or in China and do not have situations of strikes.

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH (Uttar Pradesh): In the Soviet Union there are candidates who contest as trade unioniss.

SHRI VASANT SATHE: I know of that trade union. That is the society. It is not like our trade unions registered under the Indian Trade Unions Act—seven people get together and become a union and 24 unions in an industry and all competing with each other to get more wages and less work! What kind of chaos....

SHRI CHATURANAN MISHRA: This is what the system has developed.

SHRI VASANT SATHE: This is not a dialogue. I am not wanting to score debating points here, I am saying that let this House, we as custodians of the welfare of this country, as the representatives of our people...

SHRI SUKOMAL SEN: What about coal?

SHRI VASANT SATHE: You do not want that? (Interruptions)

AN HON. MEMBER: Say something about coal.

SHRI VASANT SATHE: If you want more coal, then you must produce more coal, and output-man-shift must increase. Sir, the output-man-shift in underground mines after nationalisation, even after mechanisation, came down from 0.54 to 0.52, after mechanisation, after investing hundreds of crores of rupees on mechanisation. The OMS has come down. Sir, in no country in the world, socialist or otherwise, is the OMS so low. In China, where 97 per cent of coal is produced under mines, the output-man-shift is 2.1 tonne per man per day. And what is the wage that they get? The Government or the people have not themselves given fair wage to the coalminers. Sir, in China they get Rs. 11 per tonne. Produce 2 tonnes, get Rs. 24. In India, for producing half a tonne of coal, a coalminer gets about Rs. 98 per day. Sir, please compare this with the per capita income of the country. You talk of the poor people? The per capita income of the country is about 260 dollars or Rs. 3000 per annum. And here is an employee who gets Rs. 24000 per annum. And yet you say that he should not produce even half-a-tonne of coal? Is that fair to the people of this country? This is what I am asking. Those who want the welfare of the country, welfare of the poor people....(Interruptions) Sir, we must help in producing and that can happen only if all of us put our minds together and work collectively in a system of participatory democracy in order to produce more. If you want to have Tuticorin, Singreni in Andhra Pradesh must produce more coal. I am glad to say that because of participatory attitude.....

SHRI SUKOMAL SEN: What is participatory democracy? Please explain.

SHRI VASANT SATHE: That also is difficult for you to understand. It means socialism.

SHRI SUKOMAL SEN: Socialism of Mr. Vasant Sathe.

SHRI VASANT SATHE: Socialism is participatory democracy. All those who take part in the economic activity and those who are responsible for economic activity participate. My dear friend, that is participatory democracy. I think I will have to give him my book ultimately.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BAPU KALDATE): Why don't you say everything through me instead of saying to him directly? (*Interruptions*)

SHRI VASANT SATHE: I think it is high time in this country that this Parliament take cognizance of this fact that heavy investment cannot go without generating resources, without production, without productivity. I am afraid that in the coal sector, you cannot go on with this vicious cycle of increasing costs, increasing prices, etc. How long will you do it? We have already incurred losses. The cumulative loss today is 1200 crores in 12 years. Can you go on investing money and spending like this? So, it is time that everyone takes it seriously and tries to achieve the objectives. This is the objective of this Bill. Ultimately this Bill has been brought to plug the loopholes. After so many years, they discover a technical linking and say that this amount should have been kept apart for the coal at the stack. Shri Ashwini Kumar Ji said that we should decide it once for all. We have decided that this will be included in the amount. That is why this Bill has been brought. I am glad the House gave me an opportunity to clarify certain points. You have to get an idea and remove some cobwebs. There is a saying in Marathi which I will quote.

ये थे समस्त दहिरे बसतात ढोक
का भाषणे मधुरस करशी अनेक
हे मूर्ख ह्यांस किंवदंहि नसे विवेक
कोकील वर्ण वधुनी म्हणतील काक ।

**श्री चतुरानन मिश्र** : यह अच्छी बात हुई कि कोल नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल के साथ-साथ साठे साहब की बुक अमेंडिल बिल भी पास हो गया। क्या उन्होंने इसको सुधार दिया ? **(व्यवधान)**

**श्री बसंत साठे** : एक भी लाइन नहीं चेंज हुई है।

**श्री चतुरानन मिश्र** : एक बात कहना चाहुंगा कि आपने कहा है कि 150 मीलियन टन उत्पादन कर रहे गर कोल उद्योग को मुनाफे में लाना चाहते हैं तो फिर पूरी कपेसिटी का 250 मिलियन टन का इस्तेमाल कीजिए। भ्रम में मत रहें। आप फिर अगले बार पार्लियामेंट में आयेंगे, कहेंगे कि 250 करोड़ हम को दे दीजिए नहीं तो कोल उद्योग नहीं चलेगा मेरा कहना है कि कपेसिटी के मुताबिक उत्पादन करें। कम से कम **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BAPU KALDATE): You are again going into a dicussion. छोड़ दीजिए। एक मिनट में कुछ नहीं होने वाला है।

**श्री राम नरेश कुशवाहा** (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, मैं मंत्री जी को वचन से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है हम मजदूरों को उद्योग में शेयर मानेंगे। तो क्या कर्म में भी शेयरर मानने के लिए तयार हैं और लाभ और हानि दोनों में शेयरर मानने के लिए तयार हैं? और कब से ?

**श्री वसन्त साठे** : तयार हैं। फौरन तयार हैं।

**उपसभाध्यक्ष (डा० बापू कालदाते)** : मैं समझता हूं चतुरानन जी आपका जो प्रस्ताव है उसको वापस लेने की इजाजत मांगी है.?

**श्री चतुरानन मिश्र** : मैंने कहा है ठीक है।

**The Resolution was, by leave withdrawn.*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BAPU KALDATE): We shall now take up the Bill.

The question is:

"That the Bill further to amend the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972 and the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

*The motion was adopted.*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BAPU KALDATE): We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

*Clauses 2 to 20 were added to the Bill.*

*clause 1, the Enacting formula, and the Title were added to the Bill.*

SHRI VASANT SATHE: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

*The question was put and the motion was adopted.*

---

*For the text of the Resolution, vide cols 283 of the Debate dated the 1st December, 1986.